बी०ए०- खण्ड - II
अर्थशास्त्र (स०)
भारतीय अर्थशास्त्र - तृतीय पत्र

डॉ. विपिन कुमार
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
आर०आर०एस० कॉलेज मोकामा
पी०पी०यू० - पटना.

"GREEN REVOLUTION"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
04 APRIL - SATURDAY
Appointments 095-271 • WK-14

प्रश्न : हरित क्रान्ति क्या है ? भारतीय कृषि पर हुए इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। What is 'Green Revolution'?

उत्तर : 'हरित क्रान्ति' से तात्पर्य आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 1966-67 में हमारे देश में 'हरित क्रांति' की शुरुआत की गई। इसके 1967-68 शुरुआत का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता 'प्रो० नारमन बोरलॉग' को जाता है लेकिन भारत में एम० एस० स्वामीनाथन को इसका जनक (father) कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में (दूसरी पंचवर्षीय) फोर्ड फाउंडेशन द्वारा कृषि उत्पादन एवं दक्षता को बढ़ावा देने एवं विभिन्न तरीकों को अपनाने हेतु भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। विशेषज्ञों की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा सात जिलों को चयनित (देश में) कर एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। इस कार्यक्रम का नाम ~~आई० ए० डी० पी०~~ IADP (Intensive Agricultural District Programme) ('गहन कृषि जिला कार्यक्रम' (IADP)) अर्थात् समन्वित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नाम से जाना गया।

05 096-270 SUNDAY

ज्ञातव्य है कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। उस समय अर्थात् आजादी के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। आजादी के बाद ही बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था— जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका प्रमुख कारण कृषि को लेकर अंग्रेजी शासन की गलत नीतियाँ थीं। आजादी के बाद देश की कुल जनसंख्या 30 करोड़ के लगभग थी और उस समय कृषि क्षेत्र का लगभग 10 प्र.श. हिस्सा ही सिंचाईयुक्त था।

देश में अकाल के बाद खाद्यान्न की काफी कमी महसूस की जाने लगी। उस दौरान देश के सात राज्यों के सात जिलों (चयनित) में इसे शुरू किया गया जिसे (IADP Intensive Agriculture District Programme) अर्थात् इसे 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' नाम दिया गया। देश में यह प्रयोग सफल रहा तथा वर्ष 1966-67 में हमारे देश में 'हरित क्रांति' को औपचारिक रूप से अपनाया गया।

इस कार्यक्रम में उच्च उपज देनेवाली प्रजाति कार्यक्रम को मात्र पाँच फसलों के व्यापक उत्पादन के ऊपर केन्द्रीकृत किया गया था, यथा, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा — फलस्वरूप यह नई रणनीति सिर्फ कुछ खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित रह गयी और (अखाद्यान्न) गैर-खाद्यान्न फसलों का कृषि क्षेत्र से लगभग सफाया सा हो गया। कालान्तर में, सिर्फ गेहूँ का उत्पादन ही कृषि क्रांति का असली प्रतिफल रहा अर्थात् कृषि क्रांति का असली लाभ सिर्फ गेहूँ को ही मिला। देश में कृषि क्रांति के इस रूप को 'हरित क्रांति' का नाम इसलिए दिया गया कि इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ पहुँची।

देश में हरित क्रान्ति के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आयी है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, कृषकों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, इसके साथ ही कृषि आधिक्य में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय खाद्यान्न की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए "हरित क्रांति" का सूत्रपात किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो 'कृषि उत्पादन में अभ्वृद्धि को 'हरित क्रांति' के नाम से जाना गया।

देश में हरित क्रांति की उपलब्धियों को कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में देखा जा सकता है इसे निम्नलिखित रूप से चित्रित किया गया है:

(I) कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार : इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित तकनीकी एवं संस्थागत सुधार हुए हैं :

(i) रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
(ii) आधुनिक (उन्नतशील) किस्म के बीजों के प्रयोग में वृद्धि
(iii) सिंचाई की सुविधाओं में लगातार वृद्धि
(iv) पौध संरक्षण पर विशेष ध्यान
(v) सघन खेती / बहुफसली कृषि उपज को बढ़ावा
(vi) आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग
(vii) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं सुविधा
(viii) कृषि उद्योग निगम
(ix) विभिन्न निगमों की स्थापना : राष्ट्रीय बीज निगम (1963) (विश्व बैंक की मदद से), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (1963), राष्ट्रीय बीज परियोजना (विश्व बैंक की मदद से), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नेफेड), कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, खाद्य निगम, उर्वरक साख गारन्टी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इत्यादि स्थापित किये गए।
(x) मृदा परीक्षण
(xi) भूमि संरक्षण
(xii) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा एवं विकास

इस सभी के अतिरिक्त देश भर में ~~[illegible]~~ कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए, जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण और इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की गयी है।

(2) कृषि उत्पादन में सुधार : कृषि उत्पादन के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार दिखलाया जा सकता है :

(i) उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि
(ii) परम्परागत एवं रूढ़िवादी कृषि स्वरूप में परिवर्तन
(iii) कृषि कार्य के क्षेत्र में बचतों में अधिक वृद्धि
(iv) कृषि के अग्रगामी एवं प्रतिगामी संबंधों में मजबूती .
(v) अन्य कई कृषि उत्पादन कार्यों में व्यापक सुधार

अतः हम यह कह सकते हैं कि देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि आगतों एवं कृषि उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। अतः अब इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों को और अधिक कारगर ढंग से लागू कर कृषि क्षेत्र का और अधिक विस्तार किया जाय एवं अधिकाधिक कृषि उत्पाद का निर्यात कर विदेशी मुद्रा का लाभ कमाया जा सके।

हरित क्रान्ति का विस्तार : हरित क्रान्ति के मुख्यतः दो चरण हैं :

(1) प्रथम चरण : (1966-67 से 1980-81) .
(2) दूसरा चरण : (1990

अब आवश्यकता है पूरे देश में दूसरे हरित क्रांति के विस्तार का -- इसे क्षेत्र के विस्तार हेतु बनायी गयी कार्ययोजना (2010-11) में पहले चरण में ग्रामसभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से देश पूर्वी क्षेत्र यथा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर केन्द्र सरकार विशेष ध्यान देकर विशेष योजना की सहायता से द्वितीय हरित क्रांति को तेज गति प्रदान करे।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ देश में हरित क्रान्ति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा वहीं दूसरी तरफ इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा -- जिनमें कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नांकित हैं :

(1) हरित क्रांति का प्रभाव कुछ फसलों तक ही सीमित रह गया, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार एवं बाजरा -- यहाँ तक कि इसका चावल पर भी असर नहीं पड़ा)
(2) पूँजीवादी कृषि को बढ़ावा
(3) संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं .
(4) आय की बढ़ती असमानता
(5) क्षेत्रीय असन्तुलन.
(6) आवश्यक सुविधाओं की कमी
(7) रोजगार की समस्या .

हरित क्रांति की सफलता हेतु निम्न लिखित प्रमुख सुधार प्रकाश किये जा सकते हैं:
(1) संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना।
(2) कृषि ऋण की सुविधा।
(3) सिंचाई के साधनों का विकास।
(4) रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
(5) अन्य संरचनात्मक सुधारों का विस्तार।
(6) छोटे जोत वाले किसानों को भी जोड़ना।
(7) हरित क्रान्ति का अन्य दूसरे फसलों तक विस्तार एवं फैलाव करना।
(8) समन्वित कृषि पानी नीति।

नयी कृषि नीति : केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नयी राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गयी। इस नीति के तहत सरकार ने वर्ष 2020 तक कृषि के क्षेत्र 4 प्र.श. प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा है - इस दिशा में अब तक सरकार पूरी तरह असफल रही है। 'नयी कृषि नीति (2000) का वर्णन 'इन्द्रधनुष क्रान्ति' के रूप में किया गया था। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में नयी क्रान्तियों का आगाज किया जा सके यथा,
(i) हरित क्रान्ति (खाद्यान्न उत्पादन)
(ii) श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन)
(iii) पीली क्रान्ति (तिलहन उत्पादन)
(iv) नीली क्रान्ति (मत्स्य उत्पादन)
(v) लाल क्रान्ति (मांस / टमाटर उत्पादन)
(vi) सुनहरी क्रान्ति (सेब उत्पादन)
(vii) भूरी क्रान्ति (उर्वरक उत्पादन)
(viii) ग्रे/ऑर्गेनिक क्रांति (गैर परम्परागत स्रोत)
(ix) रजत क्रांति (अण्डे / मुर्गी / बकरी / सुअर पालन) एवं
(x) खाद्यान्न श्रृंखला क्रान्ति (खाद्यान्न, सब्जी, फलों को सड़ने से बचाना) को एक साथ लेकर चलना - इसे ही 'इन्द्रधनुषी क्रांति' कहा गया।

हरित क्रांति से प्रभावित राज्य : पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु।
हरित क्रांति का प्रभाव : रबी फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल।
हरित क्रान्ति की प्रमुख विशेषताएं : सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण - प्रशिक्षण एवं शोध, पौध संरक्षण, फसल-चक्र, भूमि संरक्षण, गहन कृषि कार्यक्रम एवं किसानों को बैंकों की सुविधायें।

N.B : अगले कक्षा में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।